प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

16.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00 बजे

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का योगदान हमारी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिमला में राज्य बिजली बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार बोर्ड में कार्य के दौरान दुर्घटना में चोटिल होने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाकर मुआवजा देगी और पूर्व में चोटिल हुए कर्मचारियों को भी इस नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है, उन्हें भी पूरा हक दिया जाएगा।

जो आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें एक्सीडेंट होने के कारण चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी और जो पिछले जितने भी ओउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली का काम करते हुए जिन्हें चोट पहुंची है, उन सभी को मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी। जितनी प्रमोशनज हुई हैं, जो एएलएम की सचिवालय के कार्यालय में पड़ी है, मैं चाहता हूं उनकी प्रमोशन तत्तकाल प्रभाव से कर दी जाए।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ए.आई.एम.एस.एस. चमियाना और टांडा मैडिकल कॉलेजों में रॉबोटिक सर्जरी की शुरूआत के बाद अब जल्द ही आईजीएमसी शिमला में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयेाजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में कमला नेहरू अस्तपाल के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बैड आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसी में गाइनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा इलैक्टिव सर्जरी भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में रोबोटिक व इलैक्टिव सर्जरी का तीन महीने तक ट्रायल आधार पर प्रयोग किया जाएगा।

जागरूकता अभियान

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ व हरित दिवाली मनाने के संदेश को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर

जागरूकता अभियान आयोजित किए। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि ये जागरूकता अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम जनता को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करना था। अभियान के दौरान पोस्टर बनाने, नारा लेखन और भाषण जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को ग्रीन दीपावली के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपनी कलाकृतियों वे भाषणों के माध्यम से प्रभावशाली संदेश दिए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके सराहनीय प्रयासों के लिए प्रमाणपत्र और पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

वाईल्ड फ्लावर हॉल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। साथ ही सरकार इस सम्पत्ति की एकमात्र मालिक बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार मशोबरा रिसोर्ट के बैंक खातों में जमा सारी राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस्ट इंडिया होटल द्वारा कम्पनी में डाली गई एक सौ 36 करोड़ रूपए की पूंजी में से सिर्फ 68 करोड़ रूपए ही उसे वापिस मिलेंगे। ये मामला लगभग 30 वर्षों से न्यायालयों में लम्बित था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि ये जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।

सेना भर्ती

भारतीय सेना द्वारा 17 से 24 नवम्बर तक शिमला जिला के रामपुर के प्रिथी मिल्ट्री स्टेशन अवेरीपट्टी में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के अनुसार ये अग्निवीर भर्ती रैली शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिला के युवाओं के लिए होगी। इस बीच शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने रैली के सुचारू संचालन के लिए एस.डी.एम. रामपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने एस.डी.एम. रामपुर को एक सप्ताह के भीतर रैली स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते सारी तैयारियां पूर्ण की जा सकें।

विश्व हिंदू परिषद

विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश में मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण को निरस्त कर इन्हें समाज के अधीन करने की मांग की है। परिषद के प्रांत अध्यक्ष केश्व वर्मा ने आज चम्बा में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि परिषद इस मांग को पूरा करवाने के लिए जल्द ही प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान शुरू करेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाएगी। उन्होंने मंदिरों की आय को लेकर हाल ही में आए प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का भी स्वागत किया। केशव वर्मा ने कहा कि मंदिरों की आय व

चढ़ावे का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चढ़ावे और आय का उपयोग सिर्फ मंदिर निर्माण या रखरखाव में ही किया जाना चाहिए।